सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 12 ● अंक 199 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, बुधवार 26 अगस्त, 2026
मूल्य ₹ 3/-

मैंने देखा है कि काफी हद तक भाग्य उम्मीद के मुताबिक होता है। अगर आप अधिक भाग्य चाहते हैं तो अधिक जोखिम उठाएं। अधिक एक्टिव रहे। अधिक हिस्सा लें। -ब्रायन ट्रेसी

भारत की दहाड़, लंका पर फॉलो-ऑन... 7 | भैसें नीलाम: नगर की सरकार के... 3 | पश्चिमी यूपी में आपत्तिजनक पोस्टर... 2

रंग लाई 4PM के संपादक संजय शर्मा की मुहिम

जेपीएनआईसी को लीज पर देगी योगी सरकार

संपादक संजय शर्मा ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

» शालीमार वाले संजय सेठ का भ्रष्टाचार लील गया अलिखेश यादव का सपना

» सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला बोले ये कैसी सरकार है

□□□ 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करोड़ों रूपयों के निमार्ण से बनी लखनऊ में एक इमारत खड़ी है जिसका नाम जेपीएनआईसी है। आज खबर आयी है कि इस इमारत को सरकार ने वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के कंसोर्टियम को लीज पर देने को मंजूरी दे दी है।

यह खबर इसलिए दर्दनाक और सवाल पूछने वाली है कि जेपीएनआईसी का सच इसके पीछे की सोच और इस इमारत को बनाने वाले बिल्डर संजय सेठ पर उठे सवाल अभी भी अनउत्तरित है। हालांकि इस फैसले के आने मे देर हुई है। इस पूरे मामले में 4पीएम के संपादक संजय शर्मा की भूमिका खास तौर पर चर्चा में रही। उन्होंने अधिवक्ता मोहम्मद हैदर के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल कर जेपीएनआईसी से जुड़े फैसलों और उनकी प्रक्रिया पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। इस बिल्डिंग का निमार्ण वर्ष 2013 में शुरू हुआ था और इसे शालीमार कॉर्प लिमिटेड को बनवाने का ठेका एलडीए ने दिया था। इस प्रोजेक्ट की शुरूआती कीमत करीब दो सौ पैंसठ करोड़ रुपये थी जिसकी सांशोधित लागत प्रोजेक्ट समाप्त होते होते नवंबर 2016 तक करीब आठ सौ पैंसठ करोड़ रुपये तक पहुंची। दावा किया जा सकता है कि किसी भी सार्वजनिक परियोजना में इतनी बड़ी लागत वृद्धि मिलना मुश्किल है।

संजय सेठ मतलब बदनामी का पुलिंदा

सरकार की दलील अपनी जगह है लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती कहानी तो यहां से शुरू होती है क्योंकि इस इमारत की नींव में सिर्फ सीमेंट और सरिया नहीं है। इसमें समाजवादी सत्ता का सपना है। सरकारी खजाने का पैसा है। निर्माण को लेकर उठे सवाल हैं। वर्षों तक बंद पड़ा एक विशाल परिसर है। और इस पूरी कहानी के बीच एक ऐसा नाम है जो राजनीति और रियल एस्टेट के बीच की दूरी को खुद में समेटे हुए है और वह है संजय सेठ। वही संजय सेठ जिनकी शालीमार कॉर्प का नाम के निर्माण से जुड़ा रहा। वही संजय सेठ जो कभी समाजवादी पार्टी की आंख-नाक-कान हुआ करते थे। वही संजय सेठ जिन्हें 2016 में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा और वही संजय सेठ जो बाद में पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे और 2024 में भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार बने। वहीं संजय सेठ पर जिन पर समय समय पर बेशकीमती जमीनों को हड़पने के आरोप लगे। वहीं संजय सेठ जिनका नाम लखनऊ के साड़ी कांड में आया। संजय सेठ पर आरापों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे छापने के लिए अखबार के पन्ने कम पड़ जाएंगे।

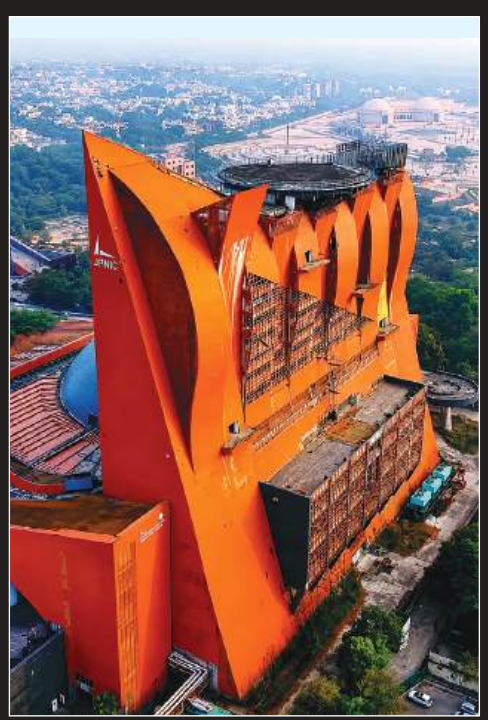

जवाब आया लीज के तौर पर

अब योगी सरकार ने इस सवाल का नया जवाब दिया है। जिस इमारत पर सरकार सैकड़ों करोड़ रुपये बहा चुकी हो उसे 30 साल के लिए निजी हाथों में चलाने के लिए दे दिया जाए। कैबिनेट ने जेपीएनआईसी को वृंदावन बॉटलर्स और रॉकवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के कंसोर्टियम को लीज पर देने का एलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे एलडीए को करीब 831 करोड़ रुपये मिलेंगे, निजी ऑपरेटर अधूरे काम को अपने खर्च से पूरा करेगा और सरकार पर आगे का बोझ नहीं आएगा।

सरकार या फिर दुकानदार?

अखिलेश यादव ने सरकार के इस फैसले पर हमला बोलते हुए सरकार को सरकार या दुकानदार तक कह दिया है और जेपीएनआईसी को निजी हाथों में देने का विरोध किया है। वही सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सवाल तैर रहे है कि अगर यह परियोजना इतनी महत्वपूर्ण थी तो इसे इतने वर्षों तक बंद क्यों रहने दिया गया? और अब जब इसे खोला जा रहा है तो तीस साल के लिए निजी संचालन क्यों? कौन सा मॉडल चुना गया? किस आधार पर चुना गया? किसने बोली लगाई? कितनी बोलियां आई? सबसे ऊंची बोली कितनी थी? और जिस कंपनी को संचालन मिला है उसके साथ सरकार का आर्थिक समझौता क्या है? सरकार के मुताबिक तीन कंपनियों/कंसोर्टियम ने बोली लगाई थी और सबसे ऊंची बोली वाले कंसोर्टियम का चयन हुआ।

जेपीएनआईसी की बदहाली पर 4PM के संपादक संजय शर्मा की पीआईएल ने मचा दिया था हड़कंप

लखनऊ स्थित जेपीएनआईसी को लीज पर दिए जाने के फैसले ने एक बार फिर सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल और उनके प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में 4PM के संपादक संजय शर्मा की भूमिका खास तौर पर चर्चा में रही। उन्होंने अधिवक्ता मोहम्मद हैदर के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल कर जेपीएनआईसी से जुड़े फैसलों और उनकी प्रक्रिया पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। संजय शर्मा की ओर से दाखिल पीआईएल के बाद इस मुद्दे ने व्यापक सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का रूप लिया। पूरी व्यवस्था पर सवाल उठे। जेपीएनआईसी की बदहाली पर कोर्ट सख्त हुआ और उसने सरकार से जवाब मांगा। हलचल हुई और यह मुद्दा जनता के दरबार में पहुंचा और विमर्श का कारण बना। इस मामले में संजय शर्मा की पहल इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि उन्होंने सवालों को केवल सार्वजनिक मंच पर उठाने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन्हें न्यायपालिका के सामने भी रखा। यही वजह है कि समर्थकों की नजर में वह ऐसे पत्रकार के तौर पर उभरते हैं जिसने सत्ता और प्रभावशाली फैसलों के सामने सवाल पूछने का जोखिम उठाया। जेपीएनआईसी प्रकरण का अंतिम निष्कर्ष न्यायिक और आधिकारिक जांच से ही तय होगा लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे को अदालत की चौखट तक पहुंचाने में संजय शर्मा की पीआईएल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सवालों का जवाब नहीं मिला

जेपीएनआईसी कोई निजी बिल्डिंग नहीं है। यह जनता की जमीन पर बनी सरकारी संपत्ति है। यह उस सरकार की परियोजना थी जिसने इसे लखनऊ की पहचान बनाने का सपना दिखाया। फिर सरकार बदली योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए। और जेपीएनआईसी का सपना सपना ही रह गया। परिसर वर्षों तक बंद रहा इमारत खड़ी रही खर्च हो चुका था काम अधूरा रहा और जनता इंतजार करती रही। यही वह दौर था जब इस परियोजना को लेकर सवाल अदालत तक पहुंचे। जेपीएनआईसी को लेकर 4पीएम के संपादक संजय शर्मा द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। लंबे समय बाद सरकार ने समाधान निकाला है कि इसे निजी हाथों में दे दो। सरकार का तर्क है कि निजी ऑपरेटर बाकी काम पूरा करेगा संचालन करेगा और एलडीए को भुगतान करेगा। 30 साल की शुरुआती लीज के साथ विस्तार का प्रावधान भी है। सुनने में मॉडल शानदार लगता है। लेकिन राजनीति में असली सवाल हमेशा यह होता है कि यहां तक पहुंचने में जनता ने कितना दिया और आगे जनता को क्या मिलेगा? जनता पूछ रही है कि जिस संपत्ति पर पहले ही 800 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके है उसका मूल्यांकन क्या है? जमीन की कीमत कितनी है? और तीस साल के संचालन की आर्थिक कीमत कितनी है? निजी कंपनी को मिलने वाले संभावित राजस्व का अनुमान क्या है? सरकार को सालाना कितना मिलेगा? और निजी ऑपरेटर कितना कमाएगा? इन सवालों के जवाब जितने पारदर्शी होंगे लीज उतनी ही विश्वसनीय होगी। वरना सवाल उठेंगे। और सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि यह कोई साधारण सरकारी भवन नहीं है। यह लखनऊ की जमीन पर खड़ी उस राजनीतिक विरासत का स्मारक है जिसे पहले समाजवादी सरकार ने बनाया और अब भाजपा सरकार निजी संचालन के हवाले कर रही है।

पश्चिमी यूपी में आपत्तिजनक पोस्टर पर भड़की सियासत

» सपा व रालोद में वार-पलटवार, सड़क पर पहुंची चवन्नी से रुपया की बात

» बागपत में अखिलेश यादव के खिलाफ लगे पोस्टर

» बैनर देख भड़के सपा नेता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बागपत। पश्चिमी यूपी में पोस्टर को लेकर बवाल मच गया है। सपा और रालोद में वार पलटवार शुरू हो गया है। बता दें बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के पास अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों वाले पोस्टर-बैनर लगाए जाने से हंगामा हो गया।

सपा ने कार्रवाई की मांग की, जबकि रालोद जिलाध्यक्ष ने आरोपियों पर कार्रवाई का समर्थन किया। बागपत में सियासी बयानबाजी के बीच पोस्टर वार सामने आया है। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे के पास सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे पोस्टर और बैनर लगाए जाने की जानकारी मिलते ही सपा नेताओं में आक्रोश फैल गया। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान समेत अन्य नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बैनर फाड़ दिए। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत करने की तैयारी है।

आपत्तिजनक पोस्टर-बैनर देख भड़के सपा नेता

हाईवे के पास अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। जानकारी मिलने के बाद सपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। बिल्लू प्रधान समेत अन्य नेताओं ने पोस्टर-बैनर फाड़ दिए।

एसपी से शिकायत की बात

सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने कहा कि बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को सुबह 11 बजे शिकायत दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि रालोद समर्थकों ने जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव की 'चवन्नी से रुपया' वाली टिप्पणी के कारण ये बैनर लगाए हैं।

रालोद जिलाध्यक्ष बोले- लगाने वाले का पता लगाकर हो कार्रवाई

रालोद जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि जिसने भी ये बैनर लगाए हैं, उसका पता लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रालोद इस तरह की राजनीति नहीं करती है और संगठन की ओर से इस तरह के पोस्टर-बैनर लगाने का कोई सवाल नहीं है।

'चवन्नी से रुपया' बयान के बाद बढ़ी सियासी तल्खी

अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच 'चवन्नी से रुपया' वाले बयान को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच बागपत में पोस्टर-बैनर लगाए जाने से विवाद और गरमा गया है। सपा ने इसके लिए रालोद समर्थकों पर आरोप लगाया है, जबकि रालोद ने आरोप से इनकार करते हुए पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करने वाले सपाइयों के खिलाफ एफआईआर

हजरतगंज स्थित नगर निगम मुख्यालय के बाहर मंगलवार को हुए प्रदर्शन में 11 नामजद और 50 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनपर रास्ता रोकने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे सपा नेता अनिस रजा के नेतृत्व में 50 से अधिक कार्यकर्ता भैंसों की नीलामी के विरोध में वहां पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर सड़क जाम की। पुलिस के समझाने पर वे उग्र हो गए, जिससे एसीपी रजनीश वर्मा और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह सहित पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। प्रदर्शन से सड़क जाम हुई, जिससे लोगों को दिक्कतें आईं और सरकारी कार्य प्रभावित हुआ। आलमबाग निवासी सपा नेता अनिस रजा, काकोरी निवासी सलीम, पारा निवासी पांडेय उर्फ बिल्लू, ठाकुरगंज निवासी अतुल यादव, तालकटोरा निवासी तुषार श्रीवास्तव, मलिहाबाद निवासी कुलदीप पासवान, तालकटोरा निवासी रोहित यादव, हुसैनगंज निवासी बाबी धानुक, तालकटोरा निवासी अबुल हाजिम, काकोरी निवासी सुजीत, गोंडा निवासी विवेक सिंह और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ चौकी इंचार्ज लालबाग दरोगा प्रदीप कुमार की तहरीर पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

महापुरुषों का सम्मान बना रहे, न बनाएं राजनीतिक हथियार: मायावती

» आंबेडकर प्रतिमा विवाद पर बसपा प्रमुख की दो टूक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से संविधान, हिजाब विवाद और डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे तनाव पर पार्टी का कड़ा रुख साफ किया है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए धर्मनिरपेक्ष संविधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सभी धर्मों की मान्यताओं, परंपराओं और रीति-रिवाजों का पूरा सम्मान होना चाहिए तथा इनमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप अनुचित है।

शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म, पर्दा या हिजाब से जुड़े विवादों पर उन्होंने सलाह दी कि ऐसे मामलों को अनावश्यक तूल देकर अदालती या कानूनी विवाद बनाने से बचना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को आपसी समझ-बूझ से इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए ताकि कोई भी तत्व इस पर संकीर्ण राजनीति न कर सके। इसके साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर बने तनावपूर्ण माहौल का तुरंत और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की मांग की है। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच, बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि ऐसे विवादों को आपसी समझ से स्थानीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए और उन्होंने चेतावनी दी कि इनका इस्तेमाल संकीर्ण राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. बीआर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया संविधान सभी धर्मों और समुदायों के लोगों को समान अधिकार देता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं के आधार पर शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने का अधिकार सभी को है। साथ ही, उन्होंने लोगों से धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों की पवित्रता का सम्मान करने की अपील की। स्कूलों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर मायावती ने कहा कि इन मामलों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने और अदालतों में कानूनी विवाद का रूप देने के बजाय, इन्हें स्कूल मैनेजमेंट, सरकार और प्रशासन के बीच आपसी समझ और सूझ-बूझ से स्थानीय स्तर पर ही सुलझाया जाना चाहिए।

बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र का मामला

बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव राजा की सीकरी में ग्राम समाज की खलिहान की भूमि पर बिना अनुमति डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने और गिराकर क्षतिग्रस्त करने के आरोप के बीच मंगलवार को सुबह से शाम तक जमकर बवाल हुआ। सरकारी भूमि पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग पर अड़े ग्रामीण शाम को उतने उग्र हो गए कि भीड़ ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर पथराव कर दिया। करीब आधे घंटे तक हुए पथराव में एसडीएम, सीओ की गाड़ी सहित एक दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अफसरों ने भागकर खुद को बचाया। पथराव से मौके पर दहशत फैल गई। पथराव में कई नागरिकों के साथ पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के घायल होने की बात सामने आई है। पुलिस फोर्स ने बलपूर्वक बवालियों को खदेड़ते हुए आंबेडकर प्रतिमा कब्जे में कर ली। पुलिस ने करीब 12 लोगों को हिरासत में ले लिया है।

मायावती ने कहा कि इस तरह के रवैये से यह पक्का होगा कि किसी को भी ऐसे विवादों की आड़ में संकीर्ण राजनीति करने का मौका न मिले। उन्होंने कहा कि बीएसपी एक अंबेडकरवादी पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के सम्मान और उनकी जान-माल व धर्म की सुरक्षा की गारंटी देती है। उन्होंने लोगों से किसी भी धर्म, धार्मिक ग्रंथों या मान्यताओं से जुड़े संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करने से बचने की अपील की।

उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलेबाज: सुरेंद्र राजपूत

» सीएम योगी के एक लाख नौकरी वाले वादे पर बोली कांग्रेस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के युवाओं के ऐलान करते हुए कहा कि सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी। अब सीएम योगी के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी वाले कितना झूठ और प्रपंच करें। 17 और 22 में आप लोगों ने कहा था कि 5० लाख नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देंगे, और अब चुनाव के 6 महीने रह गए तो कह रहे हैं कि एक लाख देंगे। 49 लाख कहां चली गई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां खाली हैं, 5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। शिक्षकों की 31 प्रतिशत कमी है, 69 शिक्षकों की भर्ती आपने नहीं की, सर्वोदय विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पुलिस में कई पद खाली हैं. सच बात यह है कि यूपी की सरकार जुमलेबाज सरकार है, जनता इंतजार कर रही है आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार नौकरियों की बहार लेकर आएगी। इसके साथ ही सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि सीएम योगी को जवाब देना चाहिए कि इन्हें साढ़े नौ साल से इन्हें बेरोजगार क्यों रखा, देखेंगे कि कैसे वायदा पूरा करेंगे।

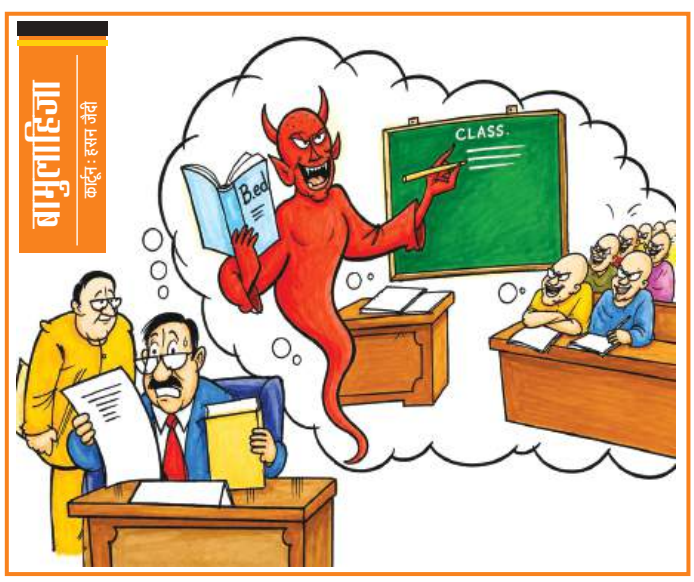

हमारा धर्म, हम तय करेंगे: ओवैसी

» स्कूलों में हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भड़के एआईएमआईएम चीफ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें स्कूल में हेडस्कार्फ पहनने की इजाजत मांगने वाली एक मुस्लिम लड़की की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

इस फैसले को इस्लाम पर हमला बताते हुए ओवैसी ने कहा कि यह तय करना जजों का काम नहीं है कि इस्लाम के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। ओवैसी ने कहा, यह हमारा धर्म है और हम तय करेंगे कि क्या जरूरी है। जज कौन होते हैं यह तय करने वाले? यह हमारे धर्म पर हमला है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही सबरीमाला से जुड़े जरूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के मामले की सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले को देख रहा है तो इलाहाबाद के जजों को इस पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश संविधान के आर्टिकल 19 और 25 के खिलाफ है। अपनी पसंद और निजता के तौर पर सिर पर हिजाब पहनने की लड़की की मांग का समर्थन करते हुए ओवैसी ने कहा, वह हिजाब अपने सिर पर पहन रही है न कि अपने दिमाग पर। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से लड़कियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा।

भैसें नीलाम : नगर की सरकार के चर्चे चारों ओर हो गए आम

सात साल बाद फिर भैंसों की नीलामी

- बढ़ी संख्या तो दोगुने से ज्यादा हुआ नगर निगम का राजस्व
- 2019 में 146 पशुओं से मिले थे 28.75 लाख,
- 2026 को 243 पशुओं की नीलामी से 58.89 लाख रुपये की आय

मो.शारिक/4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। शहर की सरकार ने इसबार कुछ ऐसा किया चर्चा बन गई। अवैध डेयरियों के खिलाफ लखनऊ नगर निगम की कार्रवाई और जब्त पशुओं की नीलामी का सिलसिला सात साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। इस नीलामी के जितना नगर निगम सक्रिय के अधिकारी व कर्मी तेजी में थे उससे कम कहीं भैसें भी नहीं थीं।

बता दें वर्ष 2019 में अवैध डेयरियों से पकड़े गए 146 पशुओं की नीलामी से नगर निगम को करीब 28.75 लाख रुपये का राजस्व मिला था। वहीं अब 24 अगस्त 26 को 243 पशुओं की नीलामी कर नगर निगम ने 58.89 लाख रुपये की आय अर्जित की है।दोनों नीलामियों के बीच करीब सात साल का अंतर है, लेकिन दोनों मामलों में एक समानता यह रही कि अवैध डेयरियों पर कार्रवाई के बाद जब्त पशुओं को नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई गई।

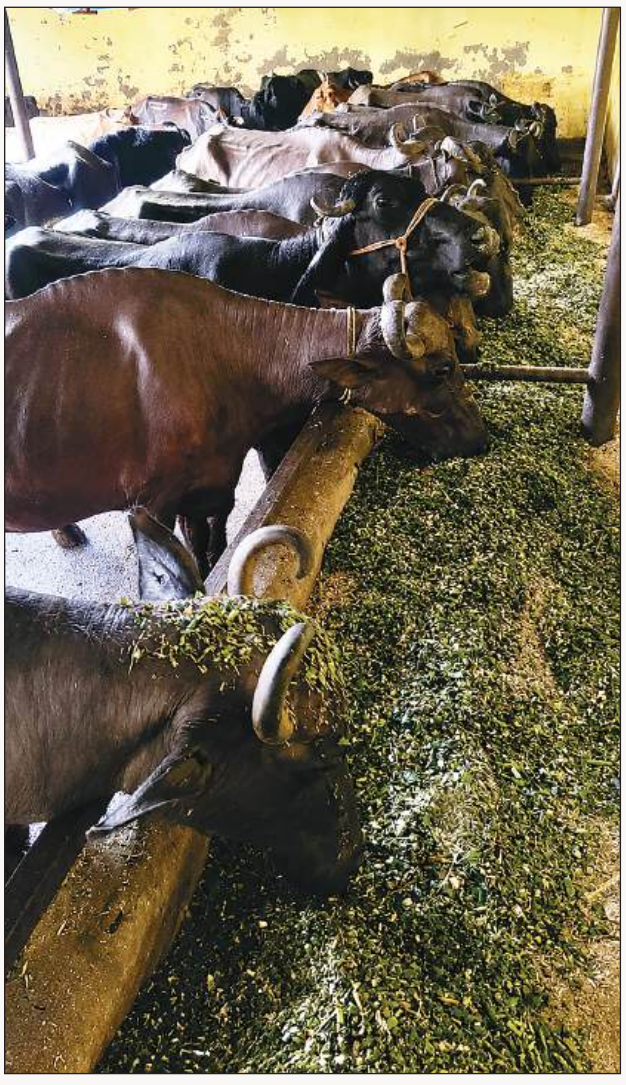

2026 में 243 पशुओं की नीलामी

सात साल बाद पारा क्षेत्र में अवैध डेयरियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी संख्या में पशु पकड़े गए। नगर निगम की कार्रवाई में कुल 243 पशु कब्जे में लिए गए। निर्धारित अवधि में जुर्माना देकर पशु नहीं छुड़ाए जाने के बाद नगर निगम ने इनकी नीलामी का निर्णय लिया था 24 अगस्त 2026 को नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकनाथ सभागार में खुली बोली के जरिए 243 पशुओं की नीलामी कराई गई। नीलामी से नगर निगम को कुल 58.89 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।नगर निगम ने नीलामी को लेकर यह भी व्यवस्था की थी कि जिन पशुपालकों के पशु कार्रवाई में पकड़े गए हैं, वे स्वयं या किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से नीलामी में अपने पशु दोबारा नहीं खरीद सकेंगे।

2019 में 146 पशुओं की हुई थी नीलामी

वर्ष 2019 में नगर निगम ने अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी संख्या में पशुओं को जब्त किया था। इसके बाद नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। दिसंबर 2019 में 146 पशुओं की नीलामी हुई थी, जिससे नगर निगम को करीब 28 लाख 75 हजार

150 रुपये की आय हुई थी। उस समय नीलामी की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे थे। पशुओं को मौके पर देखे बिना बोली लगाए जाने और कुछ पशु मालिकों के परिचितों के दूसरे नामों से बोली में शामिल होने के आरोप सामने आए थे। नगर निगम की ओर से हालांकि प्रक्रिया को पारदर्शी बताया गया था।

नीलामी के दौरान डटे रहे वरिष्ठ अधिकारी

नीलामी की पूरी कार्रवाई के दौरान नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव, वित्त एवं लेखा अधिकारी महामिलिंद लाल, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह, विनय राय, पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा तथा जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह समेत संबंधित अधिकारी नीलामी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में खुली बोली की प्रक्रिया पूरी कराई गई और नीलामी के बाद प्राप्त राजस्व को नगर निगम के खाते में जमा कराया गया।

सात साल में नीलामी का आंकड़ा और रकम दोनों बढ़े

आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2019 में 146 पशुओं की नीलामी से करीब 28.75 लाख रुपये मिले थे। वर्ष 2026 में पशुओं की संख्या बढ़कर 243 हो गई और नीलामी से मिलने वाला राजस्व भी बढ़कर 58.89 लाख रुपये पहुंच गया।

2019- 146 पशु- 28.75 लाख

2026- 243 पशु- 58.89 लाख

यानी सात साल में नीलाम किए गए पशुओं की संख्या करीब 67 प्रतिशत बढ़ी, जबकि नगर निगम की नीलामी आय करीब 105 प्रतिशत बढ़ गई।

कार्रवाई के बावजूद सवाल बरकरार

2019 में भी अवैध डेयरियों से पशु जब्त कर उनकी नीलामी करनी पड़ी थी और 2026 में भी नगर निगम को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। सात साल में नीलामी का आंकड़ा और राजस्व भले ही बढ़ गया हो, लेकिन सवाल अब भी वही है कि शहर में अवैध डेयरियों पर स्थायी रोक क्यों नहीं लग पा रही है? नगर निगम की कार्रवाई के बाद पशुओं की नीलामी से राजस्व तो मिल रहा है, लेकिन असली चुनौती यह है कि अवैध डेयरियां दोबारा संचालित न हों और शहर के रिहायशी इलाकों में पशुपालन से होने वाली समस्याओं पर स्थायी रूप से अंकुश लगे। 2019 में 146 पशु से 28.75 लाख और 2026 में 243 पशु से 58.89 लाख—सात साल में आंकड़े बदले, अधिकारी बदले, जिम्मेदारियां बदलीं, लेकिन अवैध डेयरियों पर कार्रवाई और फिर नीलामी का सिलसिला जारी है।

सपा पार्षद विधायक नीलामी में मौजूद रहे

विधायक अरमान खान ने नगर निगम की नीलामी रोकने के लिए डॉ अरविंद कुमार राव को पत्र देकर नीलामी स्थगित करने की माँग की उन्होंने कहा कि नीलामी में शामिल होने के इकछुक कई लोग फिलहाल शहर में नहीं है ऐसे में उन्हें भी मौका देने के लिए आज की नीलामी स्थगित की जाए। डॉ. अरविंद कुमार राव ने इस पर जवाब देते हुए कहा नीलामी प्रकारिया आज की जाएगी सपा पार्षद दल के नेता कामरान बेग से लेकर सैयद यावर हुसैन रेशु शफीकुर्रहमान चाचा मोहम्मद हलीम बादशाह गाजी अन्य सपा पार्षद नीलामी में मौजूद रहे।

डॉ. अरविंद राव की भूमिका भी अहम

2019 की नीलामी के समय डॉ. अरविंद कुमार राव पशु कल्याण से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उस समय भी जब्त पशुओं की नीलामी की प्रक्रिया तथा निगम की ओर से उसकी पारदर्शिता को लेकर पक्ष रखा गया था। सात साल बाद 2026 में भी डॉ. अरविंद कुमार राव की मौजूदगी नीलामी प्रक्रिया के दौरान रही। इस बार नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका पहले की तुलना में अलग और महत्वपूर्ण स्तर पर रही। इस तरह 2019 की 146 पशुओं की नीलामी से लेकर 2026 की 243 पशुओं की नीलामी तक डॉ. राव इस पूरी कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नजर आते हैं।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

दुनिया वैश्विक गांव बनी सावधानी जरूरी

आज की दुनिया आइसोलेट दुनिया नहीं है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ी है। कहीं से ईंधन के लिए तो कहीं से खाद्यान्न, कहीं दवा, कहीं अन्य किसी वस्तु के लिए निर्भरता बढ़ी है। युद्ध के चलते इंटरनेशनल लोजिस्टिक सेवाएं प्रभावित हुई है। जहां तक देश की ही बात की जाएं तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि के कीमत में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा है।

आज विश्व एक वैश्विक गांव बन गया है। मतलब दुनिया का हर एक कोना एक दूसरे से संचार क्रांति से जुड़ा है। इसलिए कहीं भी कोई समस्या होती है उसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। आज की दुनिया आइसोलेट दुनिया नहीं है। एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ी है। कहीं से ईंधन के लिए तो कहीं से खाद्यान्न, कहीं दवा, कहीं अन्य किसी वस्तु के लिए निर्भरता बढ़ी है। युद्ध के चलते इंटरनेशनल लोजिस्टिक सेवाएं प्रभावित हुई है। जहां तक देश की ही बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि के कीमत में बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने लगा है। सीधी सी बात है जब आवागमन महंगा होगा चाहे वह आम आदमी, सार्वजनिक क्षेत्र या लोजिस्टिक का हो तो उसका सीधा सीधा वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ेगा ही। यही कारण है ईंधन यानी तेल के भावों में बढ़ोतरी के साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। इसके साथ ही आयात पर निर्भर वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं।

जहां तक तेल का प्रश्न है देश में खाद्य तेल और अखाद्य तेल दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। खाद्य तेलों में भी आयात पर निर्भरता अधिक है। लाख प्रयासों के बावजूद तिलहन मिशन से तिलहनों का उत्पादन तो बढ़ा है पर अभी विदेशी निर्भरता बनी हुई ही है। इसी तरह से अन्य वस्तुओं के भाव प्रभावित होने लगे हैं। जहां तक सेवा क्षेत्र का प्रश्न है स्वीगी-जोमेटो आदि सेवा प्रदाताओं ने पिछले दिनों में अपने दामों में 16 फीसदी से भी अधिक की बढ़ोतरी कर दी है। मोबाइल सेवा प्रदाताओं ने प्लानों को रिवाइज किया हैं तो उबेर-ओला जैसे सेवा प्रदाताओं ने किराया बढ़ा दिया है। हो तो यहां तक रहा हैं कि बैंकों द्वारा जमाओं पर ब्याज दर में कमी लाना शुरु कर दिया है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि लोजिस्टिक लागत बढ़ेगी तो उसका असर सभी वस्तुओं में देखने को मिलेगा। भारत सरकार वेनेजुएला से वैकल्पिक तरीके से कच्चे तेल लाने का प्रयास कर रही है तो अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। पर यह साफ हो जाना चाहिए कि कच्चे तेल की आपूर्ति जब तक सामान्य नहीं हो जाती तब तक पूरी तरह से संकट समाप्त होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इन वैश्विक हालातों के पीछे अमेरिका-ईरान की हठधर्मिता ही है। अमेरिका-इजरायल ने ईरान से लड़ाई शुरु करते समय रुस यूक्रेन युद्ध के हालातों से सबक नहीं लिया। रुस के सामने यूक्रेन पिद्दी सा देश होने के बावजूद आज तीन साल से भी अधिक समय होने के बावजूद निर्णायक स्तर पर नहीं पहुंचा है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

लोकतंत्र में शैक्षणिक आजादी की अहमियत

अविजित पाठक

जब मैंने हालिया वी-डेम एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स (शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक) को देखा, तो मुझे झटका तो लगा, लेकिन कोई ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई। झटका इसलिए लगा कि शैक्षणिक स्वतंत्रता के मामले में 179 देशों में भारत का स्थान निचले 10-20 प्रतिशत देशों में है। मेरा दुख और बेचैनी इसलिए और बढ़ गई कि 1990 के बाद से भारत की स्थिति अब तक की सबसे खराब है, यहां तक कि 1975-1977 के आपातकाल के दौर से भी नीचे है। तथापि, दो कारणों से मुझे हैरानी नहीं होती। पहला, मुझे लगता है कि हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्वतंत्रता की भावना की उम्मीद करना बहुत भोलापन होगा, खासकर ऐसे समय में जब राजनीतिक-सांस्कृतिक व्यवस्था, अपनी कथित दकियानूसी और संभावित रूप से तानाशाही वाली प्रकृति के कारण, स्वतंत्र सोच के प्रकाश से असहज बनी हुई हो।

दरअसल, ताकत का विरोधाभास यही है आप जितने अधिक शक्तिशाली होते हैं, उतने ही अधिक डरपोक भी होते जाते हैं। यह असहमति का डर है; यह एक वैकल्पिक नजरिए का डर है; और यह आलोचनात्मक सोच का डर है जो शक्तिशाली सत्ताधारी शासन, या उसके सर्वोच्च नेता की सावधानीपूर्वक बनाई गई भव्य छवि को बिगाड़ सकती है। यह भय संक्रामक है। जहां एक ओर यह उस होनहार प्रोफेसर से डरता है जो अपनी पढ़ाई और लेखन के जरिए पितृसत्तात्मक समाज, महिलाओं के प्रति नफरत और अति-पुरुषवादी धार्मिक राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर यह 19 साल के कॉलेज छात्र को भी नहीं बख्शता, मसलन, जो राजसत्ता द्वारा फैलाई धारणा से परे हटकर उमर खालिद की प्रतिभा को समझना चाहता है, या स्टेन स्वामी और प्रो. जी.एन. साईबाबा जैसे लोगों के संघर्षों और उपलब्धियों के बारे में जानना चाहता है। वहीं इस डर की तीव्रता की कल्पना कीजिए- जिस तरह हमारे राजनीतिक तौर पर नियुक्त कुछ कुलपति सत्ताधारी शासन को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और इस तरह विश्वविद्यालय के उस मूल विचार को ही कमजोर कर देते हैं जो कई ज्ञान-परंपराओं के मिलन का केंद्र होता है।

तो क्या हैरानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में, एक अन्य प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति ने कुछ जाने-माने समाज-वैज्ञानिकों का उपहास करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की, क्योंकि उन्होंने बताए

जा रहे तथ्यों' के क्रम को उलट-पलट दिया था? शायद, भारतीय ज्ञान प्रणाली की श्रेष्ठता में उनके अटूट विश्वास ने ही उन्हें आधुनिक नारीवादियों के समूह को सुधारने के लिए प्रेरित किया! संदेश साफ है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर होने वाली हर चीज का महिमामंडन करें, और आलोचनात्मक सोच की भावना को कार्ल मार्क्स, ज्यां-पॉल सार्त्र और मिशेल फूको जैसे लोगों से उधार लिया गया महज एक पश्चिमी विचार बताकर कमतर आंकें! दूसरी बात, यह अहसास होना भी उतना ही जरूरी है कि वे चतुर शिक्षाविद जो अक्सर मूल्य-तटस्थता के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और चुप रहना पसंद करते हैं, वे भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। वे भी अकादमिक स्वतंत्रता की भावना को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। भ्रामक प्रचार मशीनरी के इस दौर में, हम अज्ञानता को हथियार बनते देख रहे हैं। हम जबरदस्ती वाले राष्ट्रवाद का बदसूरत रूप देख रहे हैं; सार्वजनिक जीवन में शालीनता और बातचीत की संस्कृति का लगातार पतन होता हम अनुभव कर रहे हैं। ऐसे हालात में कोई तटस्थ कैसे रह सकता है? असल में, यह तथाकथित तटस्थता अनिवार्य रूप से यथास्थिति को मंजूरी देने जैसी है। अगर आप तटस्थ और चुप रहते हैं, जबकि आपके साथी अपने किसी लेक्चर और लेखन की वजह से परेशान, अपमानित और निलंबित किए जाते हैं, तो आप न सिर्फ एक शिक्षाविद के तौर पर नाकाम हो जाते हैं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी विफल हो रहे होते हैं; और आखिरकार, आप उन्हीं ताकतों को मजबूत करते हैं जिन्हें स्वतंत्र जांच-पड़ताल की भावना से नफरत है।

यह अच्छा होगा अगर भौतिकी और रसायन शास्त्र के प्रोफेसर भी अपनी मूल्य-तटस्थ और सुरक्षित लैब से बाहर निकलें और यह समझें कि अकादमिक स्वतंत्रता के बिना विज्ञान भी तरक्की नहीं कर सकता। इसे स्वीकार करना होगा। अगर हम बहस करने, संवाद और आजाद सोच-विचार की संस्कृति खोते रहे, तो हमारा लोकतंत्र एक तरह से सिर्फ चुनावों के जरिए चलने वाली तानाशाही बनकर रह सकता है। लोकतंत्र का भविष्य लोगों की सोचने और संसद में भेजे गए नेताओं से सवाल पूछने की क्षमता पर निर्भर करता है। और यह तभी हो सकता है जब हमारे स्कूल और विश्वविद्यालय ऐसे नागरिक तैयार करें जो बौद्धिक रूप से जागरूक हों और संवाद में यकीन रखते हों।

मानवीय मूल्यों को जीवंत करता 'टाइम बैंक'

'टाइम बैंक' की अवधारणा लोगों के अंदर प्रेम, करुणा, सहयोग की भावनाओं को विकसित करती है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर मानवीयता एवं भाईचारे की भावना भी बलवती हो रही है। 'टाइम बैंक' लोगों के अंदर से डिप्रेशन एवं समस्याओं को दूर करने में भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि, 'जब समाज पैसों के बजाय आपसी सहयोग और समय के लेन-देन पर भरोसा करने लगता है, तो वहां अकेलेपन और असमानता की दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं।'

डॉ. रेणु सैनी

आपने अनेक बैंकों के नाम सुने होंगे। क्या आपने 'टाइम बैंक' का नाम सुना है? वर्तमान समय में इसका महत्व बढ़ गया है। यह साधारण बैंकों से बिल्कुल अलग है। साधारण बैंकों में जहां रुपये से लेन-देन किया जाता है, वहीं 'टाइम बैंक' का लेन-देन 'समय' के अनुरूप होता है। इसमें समय का हिसाब-किताब किया जाता है। समय 'डेबिट और क्रेडिट' होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रुपयों का विनिमय बिल्कुल नहीं होता। यहां सब बराबर हैं। यहां पर लोगों के अमीर और गरीब की पहचान उनके समय के क्रेडिट के अनुसार जांची जाती है। इस बैंक की स्थापना डॉ. एडगर कान द्वारा की गई थी। वर्ष 1980 में उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया। इस दौरान वे अस्पताल के बिस्तर पर लाचारावस्था में पड़े हुए थे। तब उन्हें इस बात का अहसास हुआ कि यदि कोई व्यक्ति बीमार, बुजुर्ग या अक्षम हो जाता है, तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अर्थव्यवस्था और समाज ऐसे व्यक्तियों को 'व्यर्थ' मान लेता है। इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, फलस्वरूप समाज में वृद्ध व बीमार लोगों की देखभाल पर लोग समय नहीं खर्च करते। इस सोच ने उन्हें झकझोर दिया। वे स्वयं से बोले, 'भले ही बुजुर्ग, अशक्त या बीमार व्यक्ति आर्थिक रूप से काम न कर रहा हो, लेकिन उसके पास दूसरों को देने के लिए अपना कीमती अनुभव, समय और आत्मीयता तो उपलब्ध है।' एक मानवाधिकार वकील होने के कारण उन्होंने इस बात को भी महसूस किया कि सरकारी योजनाएं निर्धन और बुजुर्गों को केवल लाभार्थी मानकर दान देती हैं। इससे उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने का निर्णय लिया जहां पर सब बराबर हों। काफी विचार-विमर्श कर उन्होंने 1980 के दशक में 'टाइम बैंकिंग' नामक संस्था की नींव रखी।

डॉ. एडगर कान का कहना था कि, 'पैसा कभी भी इंसान के असली मूल्य को नहीं माप सकता। टाइम बैंक का सिद्धांत यही है कि हर इंसान का एक घंटा बराबर है यह समाज में हर व्यक्ति को यह अहसास कराता है कि उसकी और उसके समय की कीमत है।' आज के व्यस्त समय में तो 'टाइम बैंक' की महत्ता बहुत बढ़ गई है। आज लोगों को सुनने वालों की ही तलाश है। कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, बस सब बोलना ही चाहते हैं। सब अपनी परेशानियां और बातें बताने को आतुर हैं। कई देशों ने भी 'टाइम बैंक' के महत्व को समझा और इसे स्थापित किया। 'स्विट्जरलैंड' का 'ओल्ड एज टाइम बैंक' मॉडल टाइम बैंक की एक व्यावहारिक व्यवस्था को बताता है। यहां पर युवा अपने खाली समय में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की देखभाल करते हैं।

वे उनके लिए खरीदारी करते हैं, उन्हें टहलाने ले जाते हैं और उनसे घंटों गपशप करते हैं। जितने घंटे की वे सेवा देते हैं, उतने ही घंटे व टाइम उनके 'सोशल टाइम बैंक खाते' में जमा हो जाता है। जब वे खुद वृद्ध होते हैं तो वे उसी जमा समय का उपयोग अपनी देखभाल के लिए कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ नहीं खर्च करना पड़ेगा। जापान में भी 1990 के दशक में इस टाइम बैंक की शुरुआत हुई थी। वहां पर इस तरह की व्यवस्था को 'फुरुआई किप्पु' नाम से जाना जाता है। यहां अगर कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति की देखभाल में 1 घंटा बिताता है, तो उसे 1 'फुरुआई किप्पु' यानी कि 'टाइम क्रेडिट' मिलता है। लोग इन क्रेडिट्स को जमा करते हैं और भविष्य में जब उनके माता-पिता अथवा वे वृद्ध हो जाते हैं, तो वे इन क्रेडिट्स के बदले निःशुल्क सेवाएं प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन का 'फेयर शेयर टाइम बैंक' मानसिक रूप से तनावग्रस्त, अकेले अथवा बुजुर्ग व्यक्तियों को समाज से जोड़ता है।

यहां लोग अपने खाली समय में दूसरों की मदद करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का समय लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के 'आनंद विभाग' ने अगस्त, 2019 में देश के पहले आधिकारिक 'टाइम बैंक' की स्थापना करने का निर्णय लिया और इसे लागू करने की प्रक्रिया आरंभ की। आज तो अनेक गैर-सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही हैं। 'टाइम बैंक' की अवधारणा लोगों के अंदर प्रेम, करुणा, सहयोग की भावनाओं को विकसित करती है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर मानवीयता एवं भाईचारे की भावना भी बलवती हो रही है। 'टाइम बैंक' लोगों के अंदर से डिप्रेशन एवं समस्याओं को दूर करने में भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि, 'जब समाज पैसों के बजाय आपसी सहयोग और समय के लेन-देन पर भरोसा करने लगता है, तो वहां अकेलेपन और असमानता की दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं।'

रक्षाबंधन

हर भाई बहन के लिए करे ये काम

भाई-बहन के रिश्ते का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन इस वर्ष 28 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा बंधन या रिश्ता जो रक्षा सूत्र में बंधा हो। रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी के बदले भाई बहन की रक्षा का वचन लेता है। बहन की हर परेशानी में सहायता करने, उसके सुख दुख में साथ देने का काम एक भाई ही करता है। हालांकि आज के दौर में रक्षा का मतलब बहन पर प्रतिबंध लगाना, उन्हें रोकना टोंकना, घर से बाहर अकेले जाने से मना करना, कपड़ों को लेकर रोकटोक करने मात्र से है। हर भाई को राखी का फर्ज निभाते हुए बहन की रक्षा के लिए कुछ और तरीकों को अपनाना चाहिए। हर भाई को बहन के लिए इन पांच कामों को करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उनके बीच का रिश्ता मजबूत हो सके और भाई की गैरमौजूदगी में भी बहन सुरक्षित रह सके।

रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त

28 अगस्त को भद्रा सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी, जिससे संपूर्ण दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा। राखी बांधने का मुख्य शुभ मुहूर्त प्रातः 5 बजकर 57 मिनट से लेकर प्रातः 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा, अर्थात सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति तक का यह संपूर्ण काल राखी बांधने हेतु उत्तम माना गया है।

बहन को सिखाएं आत्मरक्षा के गुण

हर लड़की को आत्मरक्षा के गुण आने चाहिए। हर समय भाई बहन के साथ नहीं रह सकता है। स्कूल-कॉलेज से दफ्तर जाने और शादी के बाद ससुराल जाने पर बहन अपने भाई से दूर हो जाती है। ऐसे मौके पर बहन को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसलिए भाई बहन को आत्मरक्षा के बारे में सिखाएं। बहनों का दाखिला कराटे, बॉक्सिंग क्लास में कराएं, ताकि वह किसी अजनबी खतरे से बच सकें।

बहन को रोकें-टोकें नहीं

समाज से बहन को बचाने के लिए भाई उन पर रोक टोक लगाते हैं। इससे आप बहन की रक्षा नहीं करते, बल्कि उसे कैद करते हैं। स तरह की सोच से निकलें।

बहन का बढ़ाएं आत्मविश्वास

अक्सर लड़कियां बाहर जानें, दूसरों के सामने खुल कर अपने विचार रखने या कई छोटी-बड़ी चीजों से डर जाती हैं। इसका कारण होता है कि उन्हें आत्मविश्वास की कमी होती है। लड़कियां शारीरिक तौर पर कमजोर हो सकती हैं लेकिन हर भाई को अपनी बहन को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के साथ ही मानसिक तौर पर भी बलवान बनाने की जरूरत होती है। बहन का आत्मविश्वास बढ़ाएं। उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। बहन को अकेले बाहर जानें दें, उन्हें अपने काम खुद करने दें।

बहन को बनाएं आत्मनिर्भर

हर भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन को आत्मनिर्भर बनाएं। पिता, भाई या पति पर निर्भर रहने के बजाए जीवन में खुद के पैरों पर खड़े रहने की सीख दें। जैसे अगर बहन कॉलेज या दफ्तर जाने के लिए आप पर निर्भर है तो उसे स्कूटी या कार ड्राइव करना सिखाए और अकेले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। बहन अगर घर पर मां के साथ घरेलू कामों में हाथ बंटाती है तो उसे पढ़ाई और नौकरी के लिए प्रोत्साहित करें। आर्थिक तौर पर भी बहन को आत्मनिर्भर बनाएं।

फैसले में दें बहन का साथ

अधिकतर लड़कियों के जीवन के फैसले पहले पिता या भाई और शादी के बाद पति लेते हैं। लड़की को क्या पहनना है, कहां और क्या पढ़ना है, नौकरी और फिर शादी तक के हर बड़े फैसले में उनसे अधिक माता पिता का हस्तक्षेप होता है। रक्षा का वचन देने वाले भाइयों को बहन के अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। बहन के जीवन के फैसले उसे खुद लेने दें। उन्हें फैसले लेना सिखाएं और उनके फैसलों में साथ दें ताकि जब आप उनके पास न हों तब भी वह निडरता से अपने जीवन को किस राह ले जाना है, यह खुद तय कर सकें।

हंसना मना है

पति मरते वक्त बीवी से: अलमारी से तेरा गोल्ड सेट मैंने ही चोरी किया था! बीवी रोते हुए: कोई बात नहीं जी, पति: तेरे भाई ने तुझे 1 लाख अमानत दी थी, वो भी मैने गायब की! बीवी: मैने आपको माफ किया! पति: तेरी कमेटी के पैसे भी मैने ही चोरी किये थे! बीवी: कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी मैंने ही दिया है।

टीचर: बस के ड्राइवर और कंडक्टर में क्या फर्क है? स्टुडेंट: कंडक्टर सोया तो किसिका टिकट नहीं कटेगा, ड्राइवर सोया तो सबका टिकट कट जायेगा।

लड़का: डिअर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे जल्दी से बताओ!' लड़की: 'सच्चा प्यार' लड़का: ओए सच्चे प्यार की बच्ची कचरा गया है जल्दी फूंक मार।

आपने कभी सोचा है की पति और चाय की पत्ती में क्या समानता है? दोनों के नसीब में जलना और उबलना लिखा है और वो भी औरतों के हाथ से।

कहानी | मेंढक और चूहा

एक जंगल में एक जलाशय में एक मेंढक रहता था। एक दिन उसी जलाशय के पास से चूहा निकला। चूहे ने मेंढक को दुखी देखकर पूछा, दोस्त क्या बात है तुम बहुत उदास लग रहे हो। मेंढक ने कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, जिससे मैं ढेर सारी बातें कर सकूं। अपना सुख-दुख बताऊं।' चूहे ने कहा आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रहूंगा।'दोस्ती होते ही दोनों घंटों एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों के बीच की दोस्ती दिनों-दिन काफी गहरी होती गई। होते-होते मेंढक के मन में हुआ कि मैं अक्सर चूहे के बिल में उससे बातें करने जाता हूं, लेकिन चूहा मेरे जलाशय में कभी नहीं आता। चूहे को पानी में लाने की मेंढक को एक तरकीब सूझी। मेंढक ने चूहे से कहा कि दोस्त हमारी मित्रता बहुत गहरी हो गई है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे एक दूसरे की याद आते ही हमें आभास हो जाए।' चूहे ने हामी भरते हुए कहा कि हां जरूर, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या?' मेंढक बोला कि एक रस्सी से तुम्हारी पूंछ और मेरा पैर बांध दिया जाए, तो जैसे ही हमें एक दूसरे की याद आएगी तो हम उसे खींच लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा।' भोला चूहा एकदम इसके लिए राजी हो गया। मेंढक ने जल्दी-जल्दी अपने पैर और चूहे की पूंछ को बांध दिया। इसके बाद मेंढक ने एकदम से पानी में छलांग लगा ली। मेंढक खुश था, क्योंकि उसकी तरकीब काम कर गई। वहीं, जमीन पर रहने वाले चूहे की पानी में हालत खराब हो गई। कुछ देर छटपटाने के बाद चूहा मर गया। बाज आसमान में उड़ते हुए यह सब देख रहा था। उसने जैसे ही पानी में चूहे को तैरते हुए देखा तो बाज तुरंत उसे मुंह में दबाकर उड़ गया। दुष्ट मेंढक भी चूहे से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी बाज के चंगुल में फंस गया। मेंढक को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। वो सोचने लगा आखिर वो आसमान में उड़ कैसे रहा है। उसने ऊपर देखा तो बाज को देखकर वो सहम गया। वो भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन चूहे के साथ-साथ बाज उसे भी खा गया।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे। व्यापार में पुराने ग्राहकों से फिर से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सार्थक बातचीत होगी।

वृषभ

आपकी व्यावहारिक सोच और अनुशासन कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। व्यापार में नई रणनीति कारगर साबित होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

मिथुन
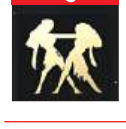
डिजिटल और आईटी सेक्टर वालों के लिए बड़ा अवसर मिल सकता है। संचार तकनीकों से व्यापार में प्रगति होगी। पुरानी गलतफहमियों का अंत होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा।

कर्क

जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन वरिष्ठों का मार्गदर्शन काम आएगा। व्यापार में उधारी देने से बचें। जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करेंगे।

सिंह

नौकरी में आत्मबल मजबूत रहेगा। व्यापारिक विस्तार की योजनाएं मूर्त रूप ले सकती हैं। व्यस्तता के बीच साथी के लिए समय न निकालने पर हल्की नाराजगी हो सकती है।

कन्या

कार्यस्थल पर आपकी बारीकी और व्यवस्थित कार्यशैली की तारीफ होगी। नया व्यापारिक सौदा पक्का हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को प्राथमिकता दें।

तुला

सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने से बड़ा लाभ होगा। व्यापारिक वादों को समय पर पूरा करें। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। धन की आवक अच्छी रहेगी।

वृश्चिक

एकाग्रता से काम करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। पुराने सौदों से आर्थिक लाभ होगा। आपसी विश्वास और भावनात्मक संबंध गहरे होंगे।

धनु
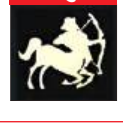
नौकरी में शिक्षा, कंसल्टेंसी और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को शानदार परिणाम मिलेंगे। विस्तार की योजना बनेगी।

मकर

कार्यक्षेत्र में आपका फोकस बेहतरीन रहेगा। नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। लव पार्टनर के साथ गंभीर मुद्दों पर सहमति बनेगी।

कुम्भ

नौकरी में आपके कार्य की प्रशंसा होगी। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से आप कारोबार में आगे रहेंगे। साथी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा।

मीन

आपकी क्रिएटिविटी रंग लाएगी। किसी बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। कारोबार है तो नए ग्राहक और नए अवसर मिलने के स्पष्ट संकेत हैं।

बॉलीवुड | मन की बात

पिता को याद कर छलके इंस्पेक्टर दया के आंसू

लोकप्रिय शो सीआईडी ने करीब दो दशक तक दर्शकों का मनोरंजन किया। इसमें एक्टर दयानंद शेट्टी ने इंस्पेक्टर दया का रोल अदा किया। हाल ही में दयानंद एक इंटरव्यू में अपने पिता को याद करते दिखे। इस दौरान वे भावुक हुए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। दयानंद शेट्टी सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में अपने पिता को याद करते दिखे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके पिता कभी थिएटर में फिल्में नहीं देखते थे। मगर, रात 9:30 बजे वे सीआईडी देखना कभी नहीं भूलते थे। दयानंद ने पिता को लेकर कहा, मेरे ख्याल से वे अनलकी इंसान थे। बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। शादी बहुत देर से की। शायद 37 साल की उम्र में। उनकी एक बहन थी, जिनके पति छोड़कर चले गए थे और उनके बच्चे थे।

उनके बच्चों की शिक्षा का वह पूरा देख रहे थे। पहले ऐसा दौर था कि बहन के बच्चों की या बहन की लाइफ सैटल नहीं हुई और भाई ने शादी कर ली तो उसे क्राइम की तरह माना जाता था। उन्होंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया। दया ने पिता को लेकर आगे बताया, लाइफ में उनकी हमेशा दिक्कत ही रही। उन्होंने बिजनेस भी किया तो खराब बिजनेसमैन रहे। हम लोग बिजनेस करते हैं तो हर चीज की कॉस्टिंग करते हैं। वो वैसे नहीं थे। वो ये मानते थे कि अगर आदमी पैसे देकर चाय पी रहा है तो वह खुश होना चाहिए। उसका पेट भरना चाहिए। ऐसे तो मुनाफा होगा ही नहीं। इस चक्कर में घाटा हो जाता था। हमारा होटल का बिजनेस था, लेकिन कभी फायदा नहीं हुआ। महीने के आखिर में यही देखना पड़ता था कि कैसे करेंगे आगे। यह बातें बताते हुए दयानंद काफी भावुक हो गए।

किसी का ज्ञान नहीं सुनूंगी : कंगना

आलोचना करने वाले रामदेव से लेकर तापसी तक सब पर भड़कीं सांसद

कंगना रनौत की युवाओं पर विवादित टिप्पणी के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। सियासी जगत के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं, योग गुरु बाबा रामदेव ने भी भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना की टिप्पणी का विरोध किया था। कंगना रनौत ने सभी को जवाब दिया है। कंगना रनौत ने कहा कि आए दिन लोग उन पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी करने वालों में से किसी ने भी उनके बराबर एक 1 प्रतिशात भी सफलता हासिल नहीं की है। ऐसे में वे किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगी। कंगना रनौत से जब पूछा गया कि आपके ऊपर टिप्पणी की जा रही है और तापसी पन्नू भी अभी फिर से बोल रही हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगी? इस पर रनौत ने कहा, देखिए हद हो चुकी है। मैं देखती हूं आए दिन इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हों, जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। सोनू सूद कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत जो मेरे चरित्र पर भद्दी टिप्पणी करती हैं, तापसी पन्नू जैसे लोग मेरे माता-पिता को और मेरी परवरिश अपमानित करती हैं। इन लोगों को मेरा सिर्फ संदेश है कि अगर आप मेरे बराबर एक प्रतिशत भी सफलता हासिल नहीं किए हैं तो मैं आपका कोई ज्ञान नहीं सुनूंगी। पहले आप कंगना रनौत बनकर दिखाएं। मैं भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। आप पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। जो लोग मुझसे अधिक माननीय हैं, मैं उनकी सलाह लूंगी। मैं असफल, भूखे-नंगे लोगों की कोई सलाह नहीं लूंगी। उन्हें जरूरत है तो उनकी मदद कर दूंगी, लेकिन उनकी सलाह नहीं चाहिए। कंगना ने आगे कहा, जहां तक बाबा रामदेव की बात है उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है सारा समाज शर्मसार है। वे सनातन के कपड़े पहनते हैं, उनको शर्मसार किया है।

मामी बोल रही हैं तो होगा कुछ गलतः कश्मीरा

गोविंदा और पत्नी सुनीता के बीच विवाद पर बोलीं बहू शाह

गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता हेडलाइन्स में बना हुआ है। शादी के कई सालों बाद दोनों पब्लिकली एक दूसरे पर भड़ास निकाल रहे हैं। गोविंदा और सुनीता के बिखरे रिश्ते पर अब उनकी बहू कश्मीरा शाह ने रिएक्ट किया है। एक समय पर बॉलीवुड के पावर कपल में शुमार गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दोनों के रिश्ते में दूरियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सुनीता का दावा है कि गोविंदा का उनकी को-एक्ट्रेस संग अफेयर चल रहा है और वो दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं, पत्नी के आरोपों पर गोविंदा का भी पलटवार देखने को मिला। गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में पड़ी फूट पर उनकी बहू कश्मीरा शाह ने रिएक्ट किया है। दरअसल, गोविंदा के भांजे कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह से मीडिया ने गोविंदा और सुनीता के बिखरे रिश्ते पर सवाल किया था। इसपर कश्मीरा गुस्से से भड़क गई। कश्मीरा चिल्लाते हुए बोलीं- अरे, जब उन लोगों ने छोड़ दिया है एक दूसरे को तो आप भी छोड़ दो ना। मैं इतना जानती हूं कि वो मेरी फैमिली है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूं। आप लोग क्यों ये सवाल पूछ रहे हो? मैं सुनीता मामी के साथ खड़ी हूं। क्या आज तक उन्होंने कभी भी आवाज उठाई है? कभी भी कहा है कि ये गलत है या वो गलत है? आज बोल रही हैं ना। तो होगा कुछ गलत। मामा-मामी के बीच कश्मीरा ने अपनी मामी सुनीता आहूजा को चुन लिया है। फैंस कश्मीरा की सच्चाई की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि सुनीता और गोविंदा के रिश्ते में पड़ी फूट के बीच फैंस और सेलेब्स दो ग्रूप्स में बंट गए हैं। कोई गोविंदा के सपोर्ट में आवाज उठा रहा है, तो कोई सुनीता का साथ दे रहा है।

13 हजार में खरीदा बेशकीमती मास्क, 36 करोड़ में बेचा

इन दिनों एक दुर्लभ मुखौटा चर्चा में है, जिसकी कीमत को लेकर बड़ा फसाद खड़ा हो गया है। दरअसल, जिस मुखौटे के लिए इतनी खींचतान चल रही है, वो कलाकृति गैबॉन का एक पारंपरिक फैंग मुखौटा है, जिसका इस्तेमाल शादियों और अंत्येष्टि जैसे अनुष्ठानों में किया जाता है। यह मुखौटा बेहद दुर्लभ है, जो कि दुनियाभर के म्यूजियम्स में एक दर्जन से भी कम हैं। यह मुखौटा सेंट्रल अफ्रीकी देश के बाहर काफी खास माना जाता है। हाल ही में इस मुखौटे को लेकर एक बुजुर्ग दंपत्ति ने एक कला डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसके पीछे की वजह है मुखौटे की कीमत। दरअसल, वह काफी अधिक मूल्यवान था। मेलऑनलाइन के अनुसार, फ़्रांस के निम्स के इस अस्सी साल के जोड़े ने 2021 में अपना घर खाली कर दिया था, जब उन्होंने एनगिल अफ़्रीकी मुखौटा बेचने का फैसला किया। उन्होंने इसे मिस्टर ज़ेड के नाम से मशहूर एक आर्ट डीलर को 129 पाउंड (13208 रुपये) में बेच दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ही महीने बाद एक नीलामी में मास्क को 3.6 मिलियन पाउंड (36,86,17320 रुपये) में बेच दिया। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने अखबार में बिक्री के बारे में पढ़ा। अब कपल मिस्टर जेड पर मुकदमा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया गया है। बताया जा रहा है कि, यह मुखौटा बुजुर्ग महिला के पति के दादा फ्रांस लाए थे, जो अफ्रीका में कोलोनियल गवर्नर थे। यह कलाकृति गैबॉन के फैंग लोगों से प्राप्त किया गया है और जिसका उपयोग शादियों और अंत्येष्टि के दौरान किया जाता है। दुनिया भर के संग्रहालयों में केवल कुछ ही पाए जाते हैं। परीक्षण के अनुसार मुखौटा 19वीं सदी का है और अदालती दस्तावेज़ इस वस्तु को अपनी दुर्लभता के मामले में असाधारण बताते हैं। निम्स में अपीलीय कोर्ट ने फैसला सुनाया कि, कपल का केस सैद्धांतिक रूप से सही प्रतीत होता है। बताया जा रहा है कि, कोर्ट ने मामले के अंत तक मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

अजब-गजब | पतली कमर करने के लिए लड़की ने किया अनोखा काम

निकलवा लीं अपनी सारी पसलियां

हर कोई ये चाहता है कि वो फिट रहे, फिट दिखे और खासकर लड़कियों की बात करें तो अधिकतर लड़कियां चाहती हैं कि उनकी कमर पतली हो और वो एकदम स्लिम-ट्रिम दिखें। इसके लिए वो खूब एक्सरसाइज करती हैं, जिम जाती हैं और फिट रहने की कोशिश करती हैं, पर सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान किया हुआ है। इस वीडियो में एक लड़की दावा कर रही है कि उसने अपनी कमर को बेहद पतला करने के लिए सर्जरी से अपनी सारी पसलियां निकलवा ली हैं। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यह वीडियो असली है या नकली। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि वीडियो में डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है। दरअसल, इस वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि लड़की अपनी कमर को आगे और बगल से दिखाती नजर आती है और कहती है, 'मेरी सारी पसलियां निकलवा दी गईं। ऑपरेशन के 15 दिन बाद मैं दुनिया की पहली महिला हूं, जिसे यह हाइपर प्रक्रिया करवानी पड़ी'। फिर वह एक प्लास्टिक बैग दिखाती है और दावा करती है कि उसमें उसकी सारी पसलियां हैं। वह आगे कहती है, 'मैं अपनी सारी पसलियों को घर ले जा रही हूं'। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है, 'एक परफेक्ट फिगर की चाहत रखने वाली महिला ने अपनी सभी पसलियां निकलवा दीं और उन्हें अपने साथ घर ले गई'। वीडियो को अब तक 2.7 मिलियन यानी 27 लाख से भी अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि 22 हजार से अधिक लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। वहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। कुछ लोगों ने वीडियो पर संदेह जताया है तो कुछ ने लड़की के दावों को सिरे से खारिज किया है। एक यूजर ने लिखा है, 'फिल्टर वहां है। उसके पीछे का दरवाजा देखिए', तो एक अन्य यूजर ने लिखा है, 'ऐसा लगता है कि वह मेज पीछे की ओर ढलानदार है'। इसी तरह एक और यूजर ने लिखा है, 'क्या आपके फर्नीचर और दरवाजे की पसलियां भी हटा दी गईं?', तो एक ने लिखा है, 'इस रील को देखकर ही मेरी हड्डियों में दर्द होने लगता है', जबकि एक यूजर ने कमेंट में पूछा है, 'पसलियां किस लिए? सूप बनाने के लिए।

भाजपा ने अच्छे दिन के बजाय आम लोगों का घर का बजट बिगाड़ दिया : खरगे

» कांग्रेस का बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है, दावा किया कि अच्छे दिन के बजाय आम लोगों का घर का बजट बिगड़ रहा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्याज और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल का जिक्र करते हुए सरकार को महंगाई नियंत्रण में विफल बताया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वोटर बढ़ती कीमतों के असर को याद रखेंगे। बुधवार को कांग्रेस ने ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया।

पार्टी ने कहा कि बीजेपी के अच्छे दिन के वादे के बजाय, लोगों के घर के बजट पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार ध्यान भटकाने वाले हथकंडों और बेतुकी बातों का सहारा लेकर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी और जनता महंगाई के मुद्दे पर सवाल उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 12 साल हो गए हैं और अच्छे दिन की सच्चाई यह है कि कभी दाल, कभी सब्जी, कभी तेल, तो कभी चीनी आम आदमी का बजट बिगाड़ती रहती है। कांग्रेस ने सोमवार को भी तेज़ी से बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। पार्टी ने पूछा था कि सरकार के अच्छे दिन लाने के दावों के बावजूद गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपना गुज़ारा कैसे करेंगे। विपक्षी पार्टी ने बार-बार मोदी सरकार पर ज़रूरी चीजों की कीमतों को काबू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि वोटर महंगाई के असर को याद रखेंगे।

एक साल में प्याज़ की कीमतें 59 प्रतिशत तक बढ़ी

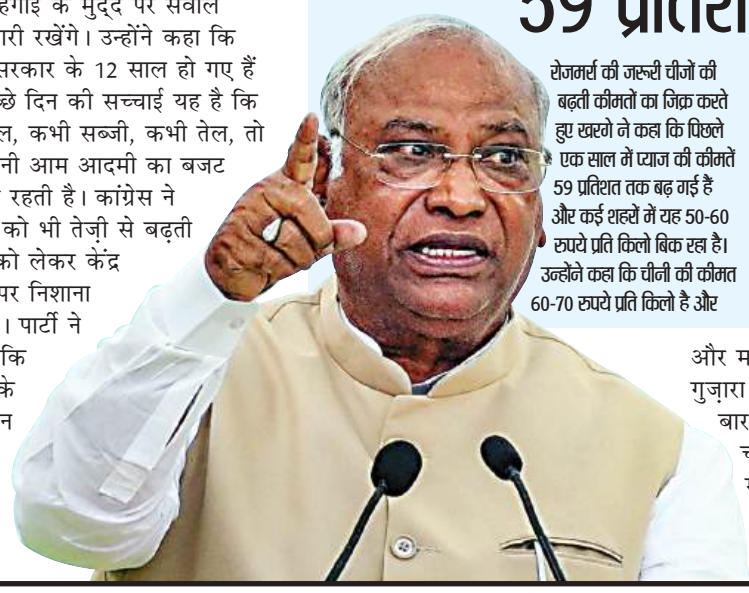

रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए खरगे ने कहा कि पिछले एक साल में प्याज की कीमतें 59 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं और कई शहरों में यह 50-60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमत 60-70 रुपये प्रति किलो है और कुछ जगहों पर यह 72 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा में बिक रहा है। खड़गे ने खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर 5.52 प्रतिशत और थोक महंगाई दर 9.78 प्रतिशत होने का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बढ़ती कीमतों का आम परिवारों पर, खासकर त्योहारों के मौसम में, क्या असर पड़ रहा है।

सुप्रीकोर्ट की दखल

स्पीकर ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्यता याचिका पर भेजा नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को, उन्हें दल-बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित करने के अनुरोध वाली तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी की याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। तृणमूल के ये 20 सांसद नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो गए हैं। लोकसभा सचिवालय ने 25 अगस्त को इन सांसदों को नोटिस जारी किया है जिसके साथ 18 जून को बनर्जी की ओर से सांसदों के खिलाफ दायर याचिका की प्रति भी भेजी गई है।

बनर्जी ने यह याचिका लोकसभा सदस्यों की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी नियमावली, 1985 के नियम छह के तहत दायर की है। सूत्रों ने बताया कि सचिवालय ने सांसदों से कहा है कि वे नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर याचिका पर अपनी राय दें। यह घटनाक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने के एक दिन बाद हुआ है जिसमें अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई जिसमें अयोग्यता की कार्यवाही पर फैसला लेने में कथित देरी पर सवाल उठाया गया था। शीर्ष अदालत ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और सदन के महासचिव को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।

तीन दशक पुराना था नजूल भूमि विवाद, जज को फोन पर हाईकोर्ट सख्त

» मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल का दावा- सरकारी जमीन बचाने और प्रभावी पैरवी था उद्देश्य

» हाईकोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता का उठाया सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ/गोंडा। गोंडा में करीब तीन दशक से लंबित नजूल भूमि विवाद अब प्रशासन और न्यायपालिका के बीच अधिकारों तथा संवैधानिक मर्यादा के सवाल को लेकर चर्चा में है। देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा मामले की सुनवाई कर रहीं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शबीना खान को फोन किए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गंभीरता से लिया है।

अदालत ने प्रथम दृष्टया इसे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने से जुड़ा मामला मानते हुए इसे आपराधिक अवमानना पर विचार करने वाली उपयुक्त पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। विवाद ने तब नया मोड़ लिया जब सिविल जज शबीना खान ने चार अगस्त को जिला जज को पत्र लिखकर पंद्रह जुलाई को मंडलायुक्त से हुई कथित टेलीफोन बातचीत की जानकारी दी. न्यायिक अधिकारी की शिकायत के अनुसार बातचीत में उनके अवकाश के साथ अदालत में लंबित मामले का भी संदर्भ आया। इसके बाद जिला जज ने संबंधित मुकदमे को गोंडा की ही समान अधिकार क्षेत्र वाली दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर दिया। स्कूल की ओर से हाईकोर्ट में मामले को देवीपाटन मंडल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग भी की गई थी। हाईकोर्ट ने फोन कॉल से जुड़े आरोपों को गंभीर माना। अदालत ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखना जरूरी है और पीठासीन अधिकारियों को निर्भय होकर न्यायिक दायित्व निभाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अदालत के अनुसार उसके सामने रखी गई बातचीत से प्रथम दृष्टया न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने का आभास होता है। इसी आधार पर मामले को आपराधिक अवमानना पर विचार के लिए उपयुक्त अदालत के सामने रखे जाने की बात कही गई।

मामला वर्ष 1997 से लंबित 'ज्योति विद्या मंदिर स्कूल बनाम नगर पालिका परिषद, गोंडा' के वाद से जुड़ा है

मामला वर्ष 1997 से लंबित 'ज्योति विद्या मंदिर स्कूल बनाम नगर पालिका परिषद, गोंडा' के वाद से जुड़ा है। विवाद कई नजूल भूखंडों को लेकर है, जो सरकारी पक्ष के अनुसार देवीपाटन मंडलायुक्त के नाम दर्ज हैं तथा कार्यालय भवन एवं अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए आरक्षित थे। प्रशासन का आरोप है कि संबंधित भूमि पर स्कूल का निर्माण किया गया और मालिकाना हक से जुड़ा विवाद करीब तीस वर्षों से दीवानी अदालत में लंबित है। मामले में यथास्थिति का आदेश भी प्रभावी रहा है और वाद साक्ष्य के चरण में बताया गया है।

भूमि के अधिकार का अंतिम निर्धारण लंबित न्यायिक प्रक्रिया से होगा

नागपाल का कहना है कि अप्रैल 26 में पदभार संभालने के बाद उन्हें इस पुराने भूमि विवाद की जानकारी मिली थी और उनका उद्देश्य सरकारी भूमि का संरक्षण तथा सरकार की ओर से लंबित मुकदमे में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना था। उनके मुताबिक उपलब्ध अभिलेखों में भूमि को सरकारी बताया गया है और वर्ष 1985 में पट्टा निरस्त होने के बाद इसे सरकार के नाम दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2008 से एक साधारण कागज के आधार पर पट्टा दर्शाया जा रहा है और संबंधित भूमि पर निजी विद्यालय संचालित है। ये फिलहाल मंडलायुक्त के दावे हैं और भूमि के अधिकार का अंतिम निर्धारण लंबित न्यायिक प्रक्रिया में होना है।

आईसा ने कॉजपा के 5 सितंबर के आदोलन का समर्थन किया

» छात्रों पर केस वापस लेने की मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के पांच सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च को समर्थन दिया है। इस मार्च में छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने और पिछले प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट और गोलियां चलाए जाने की जांच कराने की मांग की जाएगी। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि छात्र आंदोलन को जन्म देने वाले मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं।

सरकार की ओर से पहले छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद ये मामले अभी लंबित हैं। उन्होंने कहा, ''सरकार को सभी मामले पूरी तरह वापस लेने चाहिए। पैलेट और गोलियां चलाए जाने की जांच होनी चाहिए और सरकार को इसके लिए पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वामपंथी छात्र नेता ने कहा, ''आइसा की नजर में यह मामला अब भी अनसुलझा है। सरकार ने खुद मामलों को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन अब भी यह एक बड़ा मुद्दा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर मामले दर्ज हैं।'' अभिजीत दीपके के नेतृत्व वाली सीजेपी ने केंद्र के साथ बातचीत के बाद करीब एक महीने तक आंदोलन स्थगित रखने के पश्चात अब शांतिपूर्ण आंदोलन फिर शुरू करने का ऐलान किया है।

भारत की दहाड़, लंका पर फॉलो-ऑन का खतरा

» कोलंबो टेस्ट का चौथा दिन : श्रीलंका को पहली पारी में 290 रन पर ऑलआउट किया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलंबो। कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 290 रन पर ऑलआउट कर फॉलो-ऑन लागू किया। भारत द्वारा 503/9 पर पारी घोषित करने के बाद, सोनाल दिनुशा ने 103 रनों की जुझारू शतकीय पारी खेली, लेकिन वे श्रीलंका को 213 रन की बढ़त से नहीं बचा सके। सारांश जैन के दो विकेट सहित भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने टीम को मैच में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है।

बुधवार को सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन, भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में 290 रन पर ऑल-आउट कर दिया और उन्हें फॉलो-ऑन के लिए मजबूर किया। मेहमान टीम ने अपनी पारी 503/9 पर घोषित की थी, जिसके बाद मेजबान टीम 213 रन पीछे रह गई। सोनाल दिनुशा ने भारत के खिलाफ शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 162 गेंदों पर संयम के साथ 103 रन बनाए और एक बेहतरीन शतक जड़ा, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका को दूसरे सेशन में दोबारा बल्लेबाजी करनी पड़ी। दिन की शुरुआत 265/8 के स्कोर से करते हुए, श्रीलंका को फॉलो-ऑन से बचने के लिए 39 और रनों की जरूरत थी। दिनुशा ने सारांश जैन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और कुछ बाउंड्री लगाईं, साथ ही वे अपने लगातार दूसरे टेस्ट शतक के और करीब पहुँच गए।

दिनुशा ने शतक पूरा किया

दिनुशा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बाउंड्री लगाकर अपना शतक पूरा किया वे निचले क्रम के उस बल्लेबाज के तौर पर सामने आए जिन्होंने भारत को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने गाले में हुए पहले टेस्ट में 100 और 84 रन बनाए थे और यहाँ भी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अंततः 103 रन पर आउट हुए। जैन ने दिनुशा को आउट करके इस पारी में अपना दूसरा विकेट लिया केएल राहुल ने स्लिप में आसान कैच लपककर श्रीलंका की पारी 290 रन पर खत्म की।

गन्ना मजदूर से लेकर सब्जी विक्रेता तक परेशान

क्षितिजकांत

बेबाक बोल जनता खोल रही पोल

नकुड़ विस की ग्राउंड रिपोर्ट

» बोले -इस बार भाजपा छोड़ कोई आ जाए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नकुड़, सहारनपुर। नकुड़ विधानसभा में हमारी टीम ने जमीनी हकीकत जानी। खेत में काम करने वाले मजदूर से लेकर दुकानदार तक ने अपनी पीड़ा बताई।

खनन माफिया के आतंक का खुलासा

तीसरे ग्रामीण ने खनन माफिया पर गंभीर आरोप लगाए - खनन माफिया के इतने हौसले बुलंद हैं कि गांव में किसी की मृत्यु हो जाए या शादी-विवाह हो, तब भी खनन नहीं रुकता। अगर रोकने की कोशिश करो तो मारपीट पर उतर आते हैं और कहते हैं - चौकी-थाने पर पैसा जाता है, क्या कर लोगे। थाने पर शिकायत करने जाओ तो वहां पहले से सेटिंग रहती है, थाने से ही फोन कर दिया जाता है और वो भाग जाते हैं। प्रधान की भी 5 से 6 ट्रॉली खुद खनन में चल रही हैं।

आकाश आनंद और पीडीए के बारे में जानकारी नहीं

गन्ने के खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर ने कहा हम बहुजन समाज से आते हैं। हम दिन भर खेत में मजदूरी करते हैं। पत्रकार द्वारा आकाश आनंद और पीडीए के बारे में पूछने पर मजदूर ने साफ कहा -मैं आकाश आनंद और पीडीए को नहीं जानता। राजनीतिक रुख पर उसने कहा पिछली बार हमने भाजपा को वोट किया था, लेकिन इस बार वोट भाजपा को नहीं, बसपा को देंगे, क्योंकि हमारा वोट किसी और पार्टी में माना ही नहीं जाता।

सड़क के गड्ढों से परेशान ग्रामीण

दूसरे ग्रामीण ने सड़कों की बदहाली पर कहा - सड़क में सिर्फ गड्ढे भरकर खानापूर्ति की जाती है, नई सड़क बनती ही नहीं। जो पैसा आता है वो बड़े अधिकारी जेब में रख लेते हैं, सिर्फ फोटो खींचकर कागजों में काम पूरा दिखा देते हैं। उसने बताया -खनन की बड़ी-बड़ी गाड़ियों से सड़कें टूट जाती हैं, बच्चों को स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत होती है।

बिजली बिल से त्रस्त सब्जी विक्रेता

मजदूरी और सब्जी की दुकान से परिवार पालने वाले चौथे व्यक्ति ने कहा - मैं मजदूरी करता हूं, सब्जी की दुकान लगाता हूं। हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। बिजली बिल पर उसने कहा -पहले मेरा बिल 70-80 रुपये आता था। पिछले महीने 6600 रुपये का बिल आया, इस महीने 6000 रुपये का और एक बार 660 रुपये का बिल आया। समझ नहीं आता बिल कैसे बन रहा है। मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आप ही बताइए भाई साहब, मैं बिजली का बिल भरूं या घर का खर्चा चलाऊं?

घघौंड गांव यमुना नदी के किनारे अवैध खनन जारी

वहीं वहां कुछ गांवों खनन तेजी से हो रहा है। घघौंड गांव यमुना नदी के किनारे है और हरियाणा बॉर्डर जस्ट सटा हुआ है। इस कारण से यहां खनन लगातार हो रहा है । ये अवैध खनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बात को मुंह चिढ़ा रहे है जिसमें वो दावे करते हैं कि कहीं भी खनन नहीं हो रहा है।

योगी सरकार को कोर्ट का करारा झटका

» यूपी कोआपरेटिव के 48 सहायक प्रबंधकों की सेवा बहाल

» भाजपा सरकार ने 2019 में 50 सहायक प्रबंधकों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं,सपा सरकार में हुई थी भर्तियां

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी को योगी सरकार को करारा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए 48 सहायक प्रबंधकों को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया है, यह स्पष्ट करते हुए कि बिना स्वतंत्र विवेक के केवल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दें योगी सरकार ने इन भर्तियों में धांधली की बात कहके इन्हे रद कर दिया था। बाद में ये सभी कोर्ट चले गए थे।

यूपी कोऑपरेटिव बैंक (यूपीसीबी) प्रबंध समिति ने 5० सहायक प्रबंधकों की बर्खास्त किया था। सभी को एक माह का वेतन देकर नौकरी से हटा दिया गया था। ये सभी भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार केदौरान हुई थी। अरोप लगा था कि चयनित सभी सहायक प्रबंधक अफसरों और नेताओं के करीबी थे। इनके लिए भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता में भी फेरबदल किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना केवल प्रमुख सचिव के निर्देश पर उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने मनीष कुमार और 47 अन्य द्वारा दायर अलग-अलग रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने सात जून, 19 के आदेश सहित बर्खास्तगी से संबंधित आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपने संबंधित पदों पर कर्तव्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए।

यूपीसीबी इम्पलाइज एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री जय सिंह ने की थी शिकायत

यूपीसीबी इम्पलाइज एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री जय सिंह ने इन भर्तियों में हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी। उनका आरोप था कि भर्ती के दौरान नियम-कानून को ताक पर रख रसूखदारों के परिवार के सदस्यों को नौकरियां बांटी गई।

2018 में भर्ती प्रक्रिया की एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे

2017 के बाद सीएम योगी आदित्य नाथ ने अप्रैल 2018 में भर्ती प्रक्रिया की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार ने आईएएस अधिकारी पीके उपाध्याय से इस मामले की जांच कराई। जिसमें सभी शिकायतें सही पाई गई। इसके बाद भर्ती घोटाले और अन्य अनियमितताओं के आरोप में यूपीसीबी के तत्कालीन एमडी को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में जांच के बाद सरकार ने विधिक राय ली। कुल 53 पदों के लिए भर्ती हुई थी। जिसमें से सहायक प्रबंधक कम्प्यूटर के दो पदों की नियुक्तियां सही पाई गई। जबकि एक अभ्यर्थी ने चयन के बाद नियुक्ति नहीं ली थी। वर्ष 012 से 17 के बीच सहकारिता विभाग में हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। जांच में यह सामने आया कि मनचाहे उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने के लिए बिना पात्रता नियमों का पालन किए नियुक्तियाँ की गईं और ऐन मौके पर नियमों में बदलाव किए गए। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन प्रबंध निदेशकों (हीरालाल यादव और रविकांत सिंह) सहित कई अधिकारियों और सेवा मंडल के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे।अनियमितताओं के पाए जाने के बाद कई नियुक्तियों और सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी।

पाकिस्तान में के शीर्ष अस्पताल में लगी आग 15 नवजातों की मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार को एक सरकारी अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगी। इसके कारण 15 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। यह जानकारी डॉन की रिपोर्ट के अनुसार है। यह घटना राजधानी के सबसे बड़े और अच्छी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई।

जियो न्यूज ने बताया कि आग लगने की घटना में 15 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि, हताहतों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीआईएमएस की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने डॉन अखबार को बताया कि जिस वार्ड में आग लगी, वहां 15 बच्चे थे। उन्होंने कहा, हो सकता है कि रात में कुछ बच्चों को छुट्टी दे दी गई हो, इसलिए अभी हताहतों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती।

तिब्बत की बाढ़ से नेपाल में तबाही, कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहे, 28 पुलिसकर्मी लापता

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

काठमांडू। नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक आई जबरदस्त बाढ़ ने कई गांवों और प्रोजेक्ट साइट्स को तबाह दिया और 28 पुलिसकर्मी तापता हैं। अधिकारियों ने भारी जान-माल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि रसुवा के पहाड़ी जिले में स्याप्रु बेसी और तिमुरे इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। साथ ही उन्होंने भोटे कोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने को कहा है।जिला प्रशासक नरेंद्र परियार ने रॉयटर्स को बताया, हमें गांवों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट्स के बह जाने की खबरें मिली हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी जान-माल के नुकसान का कोई पक्का अनुमान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, काफी जान-माल का नुकसान हो सकता है लेकिन अभी मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि बचाव और राहत टीमों के साथ-साथ पुलिस और सेना को भी मदद के काम में लगाया गया है। उन्होंने कहा, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपने बयान में कहा, नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा सावधानी बरतें और सतर्क रहें। इस बाढ़ के कारण सुरक्षा बल के 28 जवान लापता हो गए हैं। जिन 28 सुरक्षाकर्मियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनमें से 19 नेपाल पुलिस के हैं और नौ आर्म्ड पुलिस फोर्स के हैं।

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम रोक

» यूपी पुलिस की कार्रवाई पर अंतरिम रोक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मामले में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम सुरक्षा उनके खिलाफ भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी एफआईआर पर भी लागू होगी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को संदिग्ध गतिविधियों के कारण बदलने की अपील की पीठ ने अभिषेक उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि उन्हें संबंधित एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराई जाए।

याचिकाकर्ता पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी : सीजेआई

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बार-बार एफआईआर दर्ज होने से आपकी आशंका को हम समझते हैं। हमें सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन आपकी आशंका समझ में आती है। आप हाईकोर्ट जाइए और अगर मामला बनता है तो एफआईआर रद्द कराने की मांग कर सकते हैं। तब तक हम आपको अंतरिम सुरक्षा दे सकते हैं। इसके बाद पीठ ने आदेश जारी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले से दर्ज एफआईआर या भविष्य में दर्ज की जाने वाली किसी एफआईआर के संबंध में फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

एफआईआर की कॉपी दिए जाने आदेश

गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को अगली सुनवाई तक एफआईआर की कॉपी दिए जाने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने अभिषेक उपाध्याय की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने लाया था और अन्य मामलों पर भी खोजी रिपोर्टिंग की है।

एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित : वकील

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय ने अभिषेक उपाध्याय की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी का मामला सामने लाया था और अन्य मामलों पर भी खोजी रिपोर्टिंग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित है तथा उन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता के कारण परेशान किया जा रहा है। प्रदीप राय ने यह भी कहा कि घटना के समय की सीसीटीव फुटेज से आरोपों की वास्तविकता सामने आ सकती है और इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग भी की।

महाराष्ट्र कार्यालय :- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार : मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा